



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022021-225338  
CG-DL-E-22022021-225338

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]  
No. 63]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

मामला सं. एसएसआर-एडी- 03/2021

**विषय :** चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “विस्कोस स्टेपल फाइबर” के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 7/03/2021-डीजीटीआर.—1.** एसोसिएशन मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (जिसे आगे “आवेदक संघ” अथवा “एएमएफआईआई” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय पर यथा-संशेधित सीमा प्रशुल्क(पाटित वस्तुओं पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण. और इंडोनेशिया (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) जिसमें बम्बू फाइबर, रंगा हुआ फाइबर, मॉडल फाइबर और आग प्रतिरोधक फाइबर शामिल नहीं है” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की ओर से एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात जारी रहे हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना है। आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का समय-विस्तार किए जाने का अनुरोध किया है।

### **पृष्ठभूमि**

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) जिसमें बम्बू फाइबर शामिल नहीं था” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई थी। प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 5 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डीजीएडी के माध्यम से सिफारिश किए गए थे। तत्पश्चात दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की गई थी उसे 26 जुलाई, 2010 को अधिसूचना सं. 76/2010-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।

4. एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच अधिसूचना सं. 15/9/2015-डीजीएडी दिनांक 22 जुलाई, 2015 को शुरू की गई थी। दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/9/2015-डीजीएडी के द्वारा पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने की सिफारिश की गई थी और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं.43/2016 दिनांक 8 अगस्त, 2016 के माध्यम से उसे लगाया गया था। मौजूदा शुल्क 7 अगस्त, 2021 को समाप्त होंगे।

### **विचाराधीन उत्पाद**

5. पूर्ववर्ती जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार था :

“विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) जिसमें बम्बू फाइबर” शामिल नहीं है। विस्कोस स्टेपल फाइबर सीमाशुल्क टैरिफ के अधीन विस्कोस रेयान स्टेपल फाइबर जो कॉरडेड/कॉम्प्लेन्ड न हो के रूप में वर्णित है और इसे कुछ बाजारों में “रेयान फाइबर” के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 5504.10.00 के तहत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा केवल “विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) जिसमें बम्बू फाइबर, रंगा हुआ फाइबर, मॉडल फाइबर और आग प्रतिरोधक फाइबर तक सीमित है। अन्य प्रकार के विस्कोस स्टेपल फाइबर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

### **समान वस्तु**

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और नियमावली के अधीन इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग**

8. यह आवेदन मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। घरेलू उद्योग का दोनों संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का संबंधित उत्पादक है। तथापि, किसी संबंधित कंपनी ने जांच अवधि में भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।

9. उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नियमों के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के अर्थ के तहत मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग माना है।

## कथित पाटन का आधार

### क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन गण के उत्पादकों से यह दर्शने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह दर्शने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
11. आवेदक ने वर्तमान जांच के लिए तर्कसंगत आय सहित थाइलैंड के समुचित बाजार वाले तीसरे देश के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण तदनुसार जांच की शुरुआत के उद्देश्य से किया गया है।

### ख. इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण तदनुसार जांच की शुरुआत के उद्देश्य से किया गया है।

### निर्यात कीमत

13. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय बैंक प्रभार, और अंतरराष्ट्रीय मालभाड़ा के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

### पाटन मार्जिन

14. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्याती कीमत पर विचार करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्याती कीमत से काफी अधिक है। इससे पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर अब भी निर्याती की जा रही है।

### डंपिंग और क्षति की निरंतरता / पुनरावृत्ति की संभावना

15. संबद्ध देशों से भारी पाटित आयातों के कारण पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से जारी पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण जांच अवधि में इसका कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

### निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या मौजूदा शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

## संबद्ध देश

17. वर्तमान निर्णयक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और इंडोनेशिया हैं।

### जांच की अवधि (पीओआई)

18. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 सितंबर, 2019 - 31 अक्टूबर, 2020 (12 महीने) की है जांच के अनुसार क्षति की अवधि 1 अप्रैल 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019- 31 मार्च, 2020 तथा जांच की अवधियां शामिल होंगी।

### प्रक्रिया

19. इस समीक्षा जांच में चीन जन.गण और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर, जिसमें बॉम्बू फाइबर शामिल नहीं है, के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने की सिफारिश करने वाली दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/9/2015-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी ढंग से पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण भी करेंगे।
20. संबंधित नियमावली नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

### सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in तथा ashis.dash@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एम एस वर्ल्ड फार्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एम एस एक्सल फार्मेट में हों।
22. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात् [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

### समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in तथा ashis.dash@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

## गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्यास विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

## हितबद्ध पक्षकारों के बीच प्रतिउत्तरों/अनुरोधों को शेयर करना

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।
37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**  
**INITIATION NOTIFICATION**  
New Delhi, the 22nd February, 2021  
**(Case No. SSR-AD-03/2021)**

**Subject :** Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Staple Fibre originating in or exported from China PR and Indonesia.

**F. No. 7/03/2021-DGTR.**—1. Association of Man Made Fibre Industry of India (hereinafter referred to as the ‘Applicant Association’ or ‘AMMFII’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of M/s Grasim Industries Limited , in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”), for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo Fibre, Dyed Fibre, Modal Fibre & Fire-retardant Fibre” (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as ‘subject countries’).

2. The applicant has alleged that dumped imports of subject goods have continued in spite of anti-dumping duty in force which has caused injury to the domestic industry and there is a likelihood of continuation/ recurrence of injury in case of cessation of duties. The applicant has requested for extension of anti-dumping duties on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

#### **Background**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of “Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre” from China PR and Indonesia was initiated by the Authority vide Notification No.14/6/2009- DGAD dated 19<sup>th</sup> March, 2009. Thereafter, definitive anti-dumping duties were recommended for imposition on imports from China PR and Indonesia vide Notification No. No. 14/6/2009-DGAD dated 17<sup>th</sup> May 2010 and the same were imposed vide on 26th July 2010 vide Notification No. 76/2010-Customs (ADD).
4. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated vide Notification No. 15/9/2015- DGAD dated 22<sup>nd</sup> July 2015. The extension of anti-dumping duties was recommended vide Notification No. 15/9/2015 - DGAD dated 8<sup>th</sup> July 2016 and the same was imposed by the Central Government vide notification No. 43/2016 dated 8<sup>th</sup> August 2016. The existing duties will expire on 7<sup>th</sup> August 2021.

#### **Product under Consideration**

5. The scope of the product under consideration in the previous investigation was as below

*“Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre”. Viscose Staple Fibre is described as “Viscose rayon staple fibre not carded/combed” under the Customs Tariff and is also known as “Rayon Fibre” in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation... ”*

6. The scope of product under consideration in the present investigation is restricted to only “Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo Fibre, Dyed Fibre, Modal Fibre & Fire-retardant Fibre” All other types of Viscose Staple Fibre are kept outside the scope of product under consideration.

#### **Like Article**

7. The applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the

Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

### **Domestic Industry**

8. The application has been filed by Association of Man Made Fibre Industry of India on behalf of M/s Grasim Industries Limited. M/s Grasim Industries Limited is the sole producer of the product under consideration. The domestic industry has not imported the subject goods and is not related to any importer in India. The domestic industry is related to producers of the subject goods in both the subject countries. However, none of the related entity has exported the subject goods to India in the period of investigation.
9. On the basis of information available, the Authority has considered M/s Grasim Industries Limited as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

### **Basis of alleged dumping**

#### **a. Normal Value for China PR**

10. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
11. The applicant has claimed normal value on the basis of appropriate market third country Thailand with reasonable return for the present investigation. The normal value for China PR has been determined accordingly for the purpose of initiation

#### **b. Normal Value for Indonesia**

12. The applicant has claimed the normal value of Indonesia on the basis of cost of production of subject goods in Indonesia. The normal value for Indonesia has been determined accordingly for the purpose of initiation

### **Export price**

13. The export price for subject goods for the subject countries have been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses.

### **Dumping margin**

14. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above de-minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export prices, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries have continued to be exported at dumped prices in spite of anti-dumping duty in force.

### **Likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury**

15. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry on account of significant dumped imports from the subject countries. The domestic industry has claimed that its performance has significantly deteriorated in the period of investigation due to the presence of continued dumped imports from the subject countries.

### **Initiation of sunset review investigation**

16. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury of product under consideration originating in or exported from the subject countries, and in accordance with Section 9A

of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

### **Subject Countries**

17. The subject countries in the present sunset review investigation are China PR and Indonesia.

### **Period of Investigation**

18. The period of investigation for the present investigation is 1<sup>st</sup> September 2019 – 31<sup>st</sup> October 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the period from 1<sup>st</sup> April, 2017 - 31<sup>st</sup> March 2018, 1<sup>st</sup> April, 2018 – 31<sup>th</sup> March, 2019, 1<sup>st</sup> April, 2019 – 31<sup>st</sup> March, 2020 and the period of investigation.

### **Procedure**

19. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/9/2015 - DGAD dated 8<sup>th</sup> July 2016 recommending extension of anti-dumping duty on import of Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre from China PR and Indonesia. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.
20. The provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

### **Submission of Information**

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) and [ashis.dash@nic.in](mailto:ashis.dash@nic.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
22. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

### **Time-Limit**

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) and [ashis.dash@nic.in](mailto:ashis.dash@nic.in). within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

### **Submission of Information on Confidential Basis**

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.**

36. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not accessible physically due to ongoing global pandemic.

**Non-Cooperation**

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority